

कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर बोले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष- उनका बयान कांग्रेस की ओछी मानसिकता दशार्ता है

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर राजनीति गरमा गई है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह की निम्न स्तरीय भाषा का उपयोग करना खड़गे और कांग्रेस की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। उनका गैर जिम्मेदाराना बयान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनती विश्व के लोकप्रिय नेताओं में होती है। वे हमारे देश की आन बाण और शान है। खड़गे भी राष्ट्रीय पार्टी के



अध्यक्ष हैं। भाजपा के शिविर में भाग लेने आए छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देश की जनता ने चुना है। कांग्रेस के नेताओं को अपनी वाणी को संयत रखना चाहिए। खड़गे पहले भी



मुख्यमंत्री यादव हुए शिविर में शामिल

मुख्यमंत्री मोहन यादव दोपहर तीन बजे इंदौर आए। वे एयरपोर्ट से सीधे डेली कॉलेज पहुंचे। वहां आयोजित भाजपा के एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में वे शामिल हुए। शिविर स्थल पर स्थानीय नेताओं ने उनका अगवानी की। यादव ने शिविर को संबोधित भी किया और संभ्रम और सरकार से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखी।

उन्होंने महिला आरक्षण बिल को भी मंजूर नहीं होने दिया और इसका वह जयन मना रही है।

कांग्रेस को अपनी अमर्यादित टिप्पणी पर देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए।

मप्र में 5000 फ्लैट बनाने की डीपीआर मंजूर, हितग्राहियों का चयन शुरू

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 के तहत 10 हजार फ्लैट का निर्माण होना है, जिसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) मंजूरी के लिए भोपाल गई है। 10 हजार में से 5 हजार फ्लैट बनाने की डीपीआर मंजूर हो गई है। अब जल्द ही फ्लैट का निर्माण सिंदौर और सनावदिया में होगा, क्योंकि बहुमंजिला इमारत में फ्लैट निर्माण के लिए विभिन्न विभागों से परमिशन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

परमिशन मिलते ही निर्माण कार्य और हितग्राहियों का चयन शुरू होगा। सबके पास खुद का आवास हो और मकान की कीमत भी कम हो इसके



लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। योजना के पहले चरण में इंदौर शहर और आसपास 13 जगहों पर मिली सरकारी व जमीन पर 18606 फ्लैट बनने के साथ लोगों को आबंटित होना शुरू हो गए हैं।

डीपीआर मंजूर हो गई

अब प्रधानमंत्री आवास योजना-2.0 पर काम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत सिंदौर (रंगवासा), सनावदिया, बढियाकोमा और उमरीखेड़ा में 10 हजार फ्लैट बनाने

की डीपीआर मंजूरी के लिए राज्य शासन को भोपाल भेजी गई। भोपाल भेजी गई 10 हजार में से 5 हजार फ्लैट बनाने की डीपीआर मंजूर हो गई है। सिंदौर और सनावदिया में यह 5 हजार फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके लिए टाउन एंड प्लानिंग, रेरा, बिल्डिंग परमिशन शाखा और प्रदूषण बोर्ड सहित अन्य विभागों से परमिशन ली जा रही है। परमिशन मिलते ही निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी करने के साथ फ्लैट आबंटन के लिए हितग्राहियों का चयन शुरू होगा। फ्लैट निर्माण को लेकर डीपीआर मंजूर होने की पुष्टि प्रधानमंत्री आवास योजना के अप्रसरों ने की है, जिनका कहना है कि बाकी जगहों की डीपीआर भी जल्द मंजूर होगी।

एमपी ट्रांसको ने जीआईएस सबस्टेशन के सीमित स्थान पर किया अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के इंजीनियरों ने सीमित स्थान में कौशल, दक्षता और सुविचारित कार्ययोजना का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए 132 केवी जीआईएस सबस्टेशन, ई-8 अरेरा कॉलोनी में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दूरअसल जीआईएस (गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन) तकनीक पर आधारित इस सबस्टेशन में स्थान अत्यंत सीमित होने के कारण अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर स्थापित करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य था।

इसके बावजूद एमपी ट्रांसको के इंजीनियरों ने अपनी तकनीकी दक्षता, सूक्ष्म योजना और समन्वित प्रयासों के माध्यम से कम स्थान का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए 20 एमवीए क्षमता का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर सफलतापूर्वक स्थापित



कर उसे ऊर्जीकृत किया। एमपी ट्रांसको के अतिरिक्त मुख्य अतिरिक्त श्री राजेश शांडिल्य के अनुसर इस नए ट्रांसफार्मर के स्थापित होने से न केवल भोपाल की ट्रांसफार्मेशन क्षमता में वृद्धि हुई है, बल्कि सबस्टेशन पर वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध हो गई है। अब रखरखाव (शटडाउन) के दौरान भी विद्युत आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखना संभव होगा। इस नए ट्रांसफार्मर के जुड़ने से सबस्टेशन की कुल क्षमता बढ़कर 70 एमवीए हो गई है, जो राजधानी की बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

8 साल बाद भी अधूरा है विश्राम बाग, स्विमिंग पूल और टॉय ट्रेन के इंतजार में शहरवासी, नई समय सीमा जून 2026

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

रणजीत हनुमान मंदिर के पास स्थित विश्राम बाग को सवारने का प्रोजेक्ट आठ साल का समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों को अत्याधुनिक स्विमिंग पूल और बच्चों के लिए टॉय ट्रेन जैसी मनोरंजक सुविधाएं उपलब्ध करना था। हालांकि इस दौरान तीन बार एजेंसी बदली जा चुकी है और चार बार प्रोजेक्ट की समय सीमा में बदलाव किया जा चुका है लेकिन हर बार कोई न कोई नई बाधा सामने आ जाती है। ताजा अडचन टॉय ट्रेन के ट्रैक को लेकर पैदा हुई है जिससे काम की गति एक बार फिर थम गई है।

परियोजना के तहत बच्चों के लिए टॉय ट्रेन चलाने की योजना है जिसे पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जाना था। इसमें ट्रैक और स्टेशन निर्माण की जिम्मेदारी नगर निगम की



जल्द पूरा हो जाएगा प्रोजेक्ट

विश्राम बाग के बगीचा क्षेत्र में हरियाली जरूर विकसित हुई है जिससे पर्यावरण में सुधार दिख रहा है लेकिन प्रोजेक्ट के मुख्य आकर्षण जैसे स्विमिंग पूल और टॉय ट्रेन की सुविधाएं अधूरी रहने से समूचा प्रोजेक्ट अपूर्ण नजर आता है। हालांकि निगम अधिकारियों का दावा है कि आगामी दो से तीन महीनों में सभी शेष कार्य पूरे कर लिए जाएंगे परंतु पूर्व में किए गए इसी तरह के ढवों के कारण स्थानीय लोगों में अब भी संशय बना हुआ है। प्रोजेक्ट को अपर आयुक्त अभय राजनगावकर देख रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और शहरवासियों को इसमें कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी।

थी जबकि संचालन निजी कंपनी को करना था। पूर्व में टॉय ट्रेन के ट्रैक की लंबाई 350 मीटर प्रस्तावित की गई थी जिसे अब 150 मीटर और बढ़ाकर कुल 500 मीटर करने का प्रस्ताव उठा है। इस नए विस्तार के लिए देवा

प्रस्ताव तैयार कर एमआईसी के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। एमआईसी से स्वीकृति मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी जिसका सीधा अर्थ है कि सुविधाओं के लिए जनता को अभी और लंबा

इंतजार करना होगा। विश्राम बाग कुल 11.50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से 9.10 एकड़ में बगीचा विकसित है। शेष 2.40 एकड़ हिस्से में नौ करोड़ रुपये की लागत से यह प्रोजेक्ट बन रहा है। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल भी तैयार किया जा रहा है। इसमें 50 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा इनडोर स्विमिंग पूल बनाया जाना प्रस्तावित है ताकि यहां बड़े स्तर की तैराकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकें। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्य को 2020 तक पूर्ण होना था लेकिन समय सीमा निरंतर बढ़ती रही। दो बार एजेंसी बदलने के बाद 2024 में नई कंपनी को काम सौंपा गया जिसे जून 2025 तक का समय दिया गया था। इसके बाद अर्धवर्ष को छह-छह महीने के लिए दो बार और बढ़ाया गया जिससे अब नई डेडलाइन जून 2026 तक की गई है लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसमें भी देरी होने की प्रबल संभावना है।

भुगतान में देरी से थमी प्रोजेक्ट की गति

नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक प्रोजेक्ट का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में निर्माण एजेंसी का करीब डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है जिसके कारण काम की रफ्तार धीमी पड़ गई है। स्विमिंग पूल का मुख्य ढांचा तो बनकर तैयार है लेकिन वाटर चेज सिस्टम, मोटर पंप, चेंजिंग रूम और लाइटिंग जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य अभी शेष हैं। इन कार्यों के पूरा हुए बिना पूल को शुरू करना मुमकिन नहीं है। इसके अलावा अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग एजेंसियां होने और उनके बीच समन्वय की कमी ने भी प्रोजेक्ट को प्रभावित किया है। निगम द्वारा एजेंसियों पर पेनल्टी लगाए जाने के बावजूद स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं देखा गया।

जर्जर पुल के कारण महू-घाटा बिल्लौद मार्ग पर यातायात प्रतिबंधित इन्दौर। जिला प्रशासन द्वारा इंदौर जिले के महू-घाटाबिल्लौद मार्ग पर महूगांव स्थित पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए यातायात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिवम वर्मा द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा उक्त पुल का निरीक्षण किए जाने पर इसकी स्थिति अत्यधिक खराब पाई गई, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। यह मार्ग पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र एवं इन्दौर जिले को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है, जिस पर भारी एवं यात्री वाहनों का आवागमन होता है। सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुल पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन बंद किया गया है। पुल का नवनिर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कर वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत पर की गई त्वरित कार्रवाई

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर के ग्राम अम्बामोलिया निवासी एक व्यक्ति द्वारा जनसुनवाई में की गई शिकायत पर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन के अमले ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाकर रास्ते को सुगम बनाया। ज्ञात रहे कि कल मंगलवार को सम्पन्न हुई जनसुनवाई में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा को उमेश गंगोलिया निवासी ग्राम अम्बामोलिया तहसील खुड़ैल में रास्ता पर अतिक्रमण संबंधी शिकायत की थी।

शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उनके घर के पास 9 फीट का नाला है, उसके सामने 13 फीट रोड है। नाले में गंदगी एवं कचरा के कारण हमारे स्वास्थ्य पर दुःप्रभाव पड़ रहा है। मुझ प्रार्थी की शादी भी है, जिसमें



एवं खेतों का पानी बहकर गांव की आशामती नदी में जाता है। उक्त नाले पर शिकायतकर्ता द्वारा ही अतिक्रमण किया जाना पाया गया। शिकायतकर्ता का नाले पर 3 बाय 30 फीट का अतिक्रमण पाया गया, जिसे आज हटाया गया। इसके साथ ही नाले के आसपास स्थित अन्य 12 लोगों का भी अतिक्रमण पाया गया जिसे हटाया गया। मौके पर अतिक्रमण हटाय जाकर अस्थायी रूप से रास्ता चालू करवाया गया एवं ग्राम पंचायत को पक्का नाला निर्माण हेतु निर्देशित किया गया। इस कार्रवाई की ग्रामीणों ने सराहना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर आयोजित जनसुनवाई का सकारात्मक परिणाम इस कार्रवाई को बताया। उन्होंने कहा कि इस त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है।

कलेक्टर कार्यालय में आज कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में शैक्षणिक वाहनों के सुरक्षित संचालन एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य, कॉलेज संचालक, निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विद्यार्थियों के परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश (गाईडलाइन) जारी की गईं। इस गाईडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर वर्मा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा प्रबंधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

जाएगी। किसी भी तरह समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लापरवाही पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में अपर कलेक्टर रोशन राय, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती शांता स्वामी भागवत, जिला परियोजना समन्वयक संजय मिश्रा भी विशेष रूप से मौजूद थे। बैठक के दौरान कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी स्कूल एवं कॉलेज संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़



बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी शैक्षणिक वाहनों की नियमित जांच की जाए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित भोजन उपलब्ध हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि स्कूली युनिफॉर्म और कितानों के संबंध में किसी प्रकार की मोनोपॉली नहीं रहे। अभिभावकों को परेशानी न हो। स्कूल युनिफॉर्म, कितानें एवं अन्य आवश्यक सामग्री की गुणवत्ता से उपलब्धता हो। किसी प्रकार की एकाधिकार व्यवस्था (मोनोपॉली) नहीं रहे। कलेक्टर शिवम

वर्मा ने कॉलेज परिसरों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि इसके नियंत्रण के लिए विशेष समितियों का गठन किया जाए। यह समितियां नियमित रूप से निगरानी रखें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी विद्यार्थी नशे की गतिविधियों में संलग्न न हो। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक में बताया गया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर लगाया जाना अनिवार्य है। बसों में छोटे-छोटे बच्चे सफर करते हैं, इसलिए वाहन की गति नियंत्रित रहना बेहद आवश्यक है। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।

मुश्किल लोगों को डील करने के 10 गोल्डन रूल !!!

फिर भी जिंदगी हसीन है...

dreamsachieverspune@gmail.com

दोस्तों, इस दुनिया का हर इंसान अपने आप में अनूठा और अनोखा है और इसीलिए हर किसी का इस जीवन को देखने और जीने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसलिए जीवन में कठिन लोगों से सामना होना तो सामान्य है, लेकिन उनसे निपटना थोड़ा चुनौतीपूर्ण और हॉ, ऐसे कठिन और चुनौतीपूर्ण लोग आपको कभी सहकर्मी, तो कभी पारिवारिक सदस्य या फिर सामाजिक दायरे के परिचित के रूप में मिल सकते हैं और इनका आपके जीवन में आने का मुख्य उद्देश्य आपके धैर्य, मानसिक शांति और भावनाओं पर नियंत्रण की परीक्षा लेना है। अगर आप अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को संतुलित कर लें, तो ऐसे कठिन से कठिन व्यक्ति के साथ भी सहजता से निपटा जा सकता है। साथ, आज हम इस कला को 10 गोल्डन रूल के आधे सौखते हैं-

1. हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं- हर टिप्पणी प्रतिक्रिया के लायक नहीं होती। कई बार मौन ही सबसे

प्रभावी उत्तर होता है। अपनी मानसिक ऊर्जा बचाएं और केवल जरूरी बातों पर ही प्रतिक्रिया दें। 2. दूसरों की अराजकता को अपनी समस्या न बनाएं- किसी का व्यवहार उसकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। आपका काम खुद की शांति बनाए रखना है, ना कि हर स्थिति को नियंत्रित करना या दूसरों को बदलने की कोशिश करना। 3. स्पष्ट और स्वस्थ सीमाएं तय करें- विनम्र लेकिन दृढ़ रहें। यह मेरे लिए सही नहीं है कहना सीखें। सीमाएं आत्म-सम्मान की रक्षा करती हैं और आपको मानसिक थकान, अनावश्यक दबाव और भावनात्मक शोषण से बचाती हैं। 4. उनके व्यवहार की नकल न करें- यदि सामने वाला नकारात्मक है, तो आप संतुलित रहें। आपका संयम ही आपकी ताकत है। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान बनाता है, न कि सामने वाले की प्रतिक्रिया। 5. भावनाओं नहीं, तथ्यों पर टिकें रहें- कठिन बातचीत में भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान दें। तथ्य विवाद खत्म करते हैं, भावनाएं उसे बढ़ाती हैं और आपको अधिक प्रभावी, स्पष्ट और सम्मानजनक संवाद स्थापित करने में मदद करती हैं। 6. हर किसी के सलाहकार बनने की जरूरत नहीं- हर समस्या को सुलझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी ऊर्जा को सही जगह निवेश करें और उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में आपके जीवन को आगे बढ़ाती हैं।

7. प्रतिक्रिया से पहले विराम लें- तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ा रुकें। सोच-समझकर दिया गया उत्तर हमेशा बेहतर होता है और यह आपको अनावश्यक विवाद, पछतावे और गलतफहमियों से दूर रखता है। 8. विषाक्त बातचीत से दूरी बनाएं- यदि बातचीत नकारात्मक हो रही है, तो विषय बदलें या बाहर निकल जाएं। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता और आपकी शांति किसी भी बहस या तर्क से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 9. एक कदम आगे सोचें- लोगों के व्यवहार के पैटर्न को समझें और पहले से तैयार रहें। तैयारी आपको शांति और नियंत्रित रखती है और आपको हर परिस्थितियों में बेहतर निर्णय लेने और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। 10. अपने भरोसेमंद लोगों से बात करें- अपने अनुभव साझा करें। सही लोगों से सलाह लेना मानसिक मजबूती को बढ़ाता है और आपको नए दृष्टिकोण और भावनात्मक सहारे के साथ सही दिशा में सोचने की शक्ति देता है। अंत में इतना ही कहूंगा कि कठिन लोगों से निपटना केवल एक कौशल नहीं, बल्कि आत्म-विकास की प्रक्रिया है। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, सीमाएं तय करते हैं और अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं, तब आप सिर्फ परिस्थितियों को नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा को भी बेहतर बना रहे होते हैं।

जनता की बात-पुलिस के साथ: मोहल्ला बैठकों से मजबूत हो रहा भरोसे का रिश्ता

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

शहर में पुलिस और आमजन के बीच संवाद को मजबूत बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल के तहत जनता की बात-पुलिस के साथ अभियान के अंतर्गत भंवरकुल एवं थाना क्षेत्र में मोहल्ला समिति बैठक एवं जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य न केवल लोगों की समस्याओं को सुनना है, बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास की मजबूत नींव तैयार करना भी है। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त जोन-04 आनंद कलादगी, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विशेष अग्रवाल, सहायक पुलिस आयुक्त विजय चौधरी तथा थाना प्रभारी संतोष दूधी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में

युवाओं को दिया जागरूकता का संदेश

जनसंवाद के दौरान मौजूद छात्र-छात्राओं से विशेष बातचीत की गई। अधिकारियों ने उन्हें नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने, यातायात नियमों का पालन करने और अपने उज्वल भविष्य के प्रति सजग रहने की सलाह दी। इस संवाद ने युवाओं को न केवल जागरूक किया, बल्कि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित भी किया। इंदौर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस तरह की मोहल्ला समिति बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस अधिकारियों द्वारा आमजन के बीच जाकर संवाद स्थापित करने की यह पहल लोगों में विश्वास और सहयोग की भावना को बढ़ा रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों और पुलिस के बीच परस्पर विश्वास और सहकारिता को बढ़ावा देना है। साथ ही सुरक्षा, सड़क प्रॉब्लम से बचाव, यातायात जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति लोगों को जागरूक करना भी इसका अहम हिस्सा है। बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी, छात्र-छात्राएं और नगर सुरक्षा समिति के सदस्य शामिल हुए। समस्याओं पर खुलकर हुई चर्चा कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने सीधे नागरिकों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। क्षेत्रवासियों ने कानून-व्यवस्था, यातायात, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर अपनी चिंताएं प्रकट कीं। पुलिस अधिकारियों ने इन समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।



कार्य प्रभार सौंपा गया

इंदौर (ग्लोबल हेराल्ड)। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा द्वारा प्रशासनिक कार्य व्यवस्था को दृष्टि से अपर कलेक्टर श्री नवजीवन विजय पवार को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ जनगणना कार्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।

महानगर इंदौर

भागीरथपुरा की गलियों में अचानक पहुंचे नगर निगम कमिश्नर सिंघल, रहवासियों की सीधी बात

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

भागीरथपुरा में पिछले दिनों सामने आए जल संकट के बाद क्षेत्र की स्थिति सुधारने के लिए नगर निगम लातार प्रवास कर रहा है। यहां नई पाइपलाइन बिछाने के साथ-साथ ड्रेनेज व्यवस्था और सड़कों के निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इन विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति और जमीनी हकीकत को समझने के लिए बुधवार को नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल अधिकारियों की टीम के साथ खुद मैदान में उतरे। उन्होंने भागीरथपुरा की तंग गलियों का पैदल भ्रमण कर चल रहे कार्यों का गहराई से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय रहवासियों से सीधे संवाद कर उनका फीडबैक लिया और अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता और गति सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।



विकास कार्यों की जमीनी स्थिति का अवलोकन

निरीक्षण के दौरान नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने नर्मल जल प्रदाय योजना, सीवरेज लाइन बिछाने और सड़क निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निमाणाधीन कार्य निर्धारित समय

सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। जानकारी के अनुसार, भागीरथपुरा के करीब 95 प्रतिशत हिस्सों में पाइपलाइन के माध्यम से जल आपूर्ति का कार्य पूरा हो चुका है और सुचारु रूप से पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं जिन क्षेत्रों में अभी काम शेष है, वहां टैंकरो के माध्यम से वैकल्पिक जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश

नगर निगम कमिश्नर ने भ्रमण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण और पुनर्स्थापन (रेस्टोरेशन) कार्यों की प्रतिदिन निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सके और लोगों को जल्द राहत मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को फोल्ड पर सक्रिय रहकर कार्य की गति बनाए रखने के निर्देश भी दिए। क्षेत्र के दौरान कमिश्नर ने विशेष रूप से पेयजल आपूर्ति को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने पूछा कि उन्हें कौन से समस्याएं हैं और समय पर पानी मिल रहा है या नहीं। रहवासियों ने बताया कि फिलहाल जल आपूर्ति नियमित रूप से हो रही है। कुछ लोगों ने पानी की आपूर्ति के समय को लेकर सुझाव भी दिए। इस पर कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से पानी के नमूने लें और क्लोरोनेशन प्रक्रिया को गंभीरता से लागू करें, ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल मिल सके।

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर के चर्चित भागीरथपुरा पेयजल दूषित कांड को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट के समक्ष जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। हाईकोर्ट ने 14 जून तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 16 जून को होगी।

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के कारण 35 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने मृतकों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगी हैं। कोर्ट ने इस मामले में जांच आयोग गठित किया है। पिछली सुनवाईओं में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जवाब पेश हुआ था। उसमें 18 मौतें दूषित पेयजल के कारण स्वीकरी गई थीं। इसके अलावा एक जांच समिति ने अपनी प्रारंभिक



रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने पेयजल लाइन में दूषित पानी मिलने व अन्य कारण बताए थे, लेकिन अभी तक इस मामले में गठित आयोग की तरफ से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। आयोग भागीरथपुरा के प्रभावित परिवारों से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह चुका है। कुछ परिवारों ने आयोग के समक्ष मौतों को लेकर साक्ष्य भी दिए हैं। अब पेयजल के कारण स्वीकरी गई थीं। इसके अलावा एक जांच समिति ने अपनी प्रारंभिक

विधानसभा क्षेत्र एक की भागीरथपुरा बस्ती में दूषित पानी से डारिया व हैजा फैला था। बस्ती में एक हजार से ज्यादा लोग इस कारण बीमार हुए थे और पांच सौ लोगों को अस्पतालों में भर्ती किया गया था। उपचार के दौरान 35 लोगों की इस मामले में मौत हो चुकी है। यह मामला राष्ट्रीय स्तर तक उछला था और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी भागीरथपुरा बस्ती में आए थे और प्रभावित परिवारों से मिले थे।

आबकारी वृत्त आंतरिक 2 द्वारा दोपहिया वाहन सहित 75 पाव देशी मदिरा जब्त

इंदौर (ग्लोबल हेराल्ड)। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के आदेशानुसार एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के निर्देशन में इंदौर जिले में अवेध मदिरा के



क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में मंगलवार को वृत्त आंतरिक 2 प्रभारी जया मुजान्दे ने अपनी टीम के साथ बीजलपुर क्षेत्र में सार्वकालीन गश्त के दौरान मुखबि से प्राप्त सूचना पर टेजर टाउन कॉलोनी के पीछे छापरी नामक स्थान पर दोपहिया

वाहन से 75 पाव देशी मदिरा मसाला व प्लेन के जन्त की गई। आबकारी का वाहन देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी के विरुद्ध म.प्र.आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जब्त मदिरा एवं वाहन की कुल कीमत लगभग 86000 रुपए निकाली गई है। आज की कार्यवाही में वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक जया मुजान्दे एवं आबकारी आरक्षक उम्मान मिर्जा, एलन बघेल और ड्राइवर रफीक का सराहनीय योगदान रहा।

विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर इंदौर में निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर 25 को

इंदौर (ग्लोबल हेराल्ड)। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ एवं पशुपालन एवं डेयरी विभाग, इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में 25 अप्रैल 2026, शनिवार को एक निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर पशु चिकित्सालय राज मोहल्ला, एमओजी लाइन, इंदौर में प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होकर 1 बजे तक रहेगा। शिविर में पशुपालकों एवं पशु प्रेमियों के लिए रेबीज टीकाकरण, पशु स्वास्थ्य परीक्षण, कुत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण तथा निःशुल्क औषधि वितरण जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस आयोजन का उद्देश्य पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण के साथ-साथ पशुपालकों को उन्नत पशुपालन सेवाओं से जोड़ना है। समस्त पशुपालकों, पशु प्रेमियों एवं स्वान प्रेमियों से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शिविर का लाभ उठाएं और अपने पशुओं के स्वास्थ्य की जांच एवं उपचार सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने सपरिवार किए बाबा महाकाल के दर्शन



उज्जैन (ग्लोबल हेराल्ड)। मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने आज उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। श्री मकवाना ने नंदी हॉल में बाबा महाकाल का पूजन-अर्चन कर प्रदेश में शांति, सुरक्षा एवं खुशहाली की कामना की। मंदिर के पुजारियों द्वारा शास्त्रोक्त विधि से पूजन संपन्न कराया गया एवं उन्हें शॉल-श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। दर्शन के उपरांत डीजीपी ने मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

नगर निगम के एक जोन में बवाल... महिला कर्मचारी के आरोप के बाद हंगामा और पिटाई के हालात

इंदौर (ग्लोबल हेराल्ड)। नगर निगम एक जोन से जुड़ा एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने कार्यस्थल के माहौल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, एक महिला कर्मचारी ने जोन के ही एक अधिकारी पर अनुचित स्पर्श (बेड टच) का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद महिला ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद उसकी मां मौके पर पहुंची और आक्रोश में जमकर हंगामे के साथ संबंधित अधिकारी को पिटाई कर दी। इस घटनाक्रम के बाद दफ्तर में अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर अधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अंदरखाने चर्चा तेज है। यह घटनाक्रम एक बार फिर कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। जबकि संबंधित अधिकारी के व्यवहार को लेकर पूर्व में भी कई शिकायतें निगम मुख्यालय तक पहुंची हैं। इसी बीच ये बवाल भी सामने आ गया है। अब नजर इस बात पर है कि नगर निगम प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और आगे क्या कार्रवाई होती है।

इंदौर के दो प्रमुख रूफटॉप रेस्टोरेंट सील, अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी पड़ी भारी

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर में गर्मी तेज होते ही आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अग्नि सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा और जांच के लिए भी अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों और व्यावसायिक संस्थानों में आग से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करना है। सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ प्रशासन द्वारा निरंतर कड़ी कार्रवाई की जा रही है ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

इसी अभियान की कड़ी में आज नगर निगम के जोन क्रमांक 07 और वार्ड क्रमांक 29 के अंतर्गत आने वाले पीयू 3 स्क्रीम नंबर 54 क्षेत्र में प्रशासनिक टीम ने



अनियमितताओं के चलते संस्थानों को किया गया तत्काल सील

रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा बरती गई इन गंभीर अनियमितताओं और सुरक्षा के प्रति लापरवाही को देखते हुए प्रशासन ने कठोर कदम उठाया। मौके पर ही दोनों रूफटॉप रेस्टोरेंट्स को तत्काल प्रभाव से सील करने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई तहसीलदार मल्हारगंज निधि धाकड़, भवन अधिकारी जोन 07 टीना सिंसिया, भवन निरीक्षक पीयूष मावी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की उपस्थिति में पूरी की गई।

दबिश दी। यहां भूखंड क्रमांक 13-14 और 32-33 पर स्थित भवनों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इन भवनों की

बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। सुरक्षा मानकों के अभाव के साथ-साथ यहां बिना किसी आधिकारिक स्वीकृति के किचन का संचालन भी किया जा रहा था।

सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रशासन की कड़ी चेतावनी

जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से हिदायत दी है कि अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले संस्थानों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में भी अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार के औचक निरीक्षण और सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा ताकि शहर के सभी व्यावसायिक परिसर पूरी तरह सुरक्षित हो सकें।

रातभर दमकलें बुझाती रही आग, रेलवे-डिफेंस सप्लायर कंपनियों की यूनिट भी जलकर खाक

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

इंदौर से 40 किलोमीटर दूर पीथमपुर के सेक्टर तीन स्थित हजारगो कंपनी में लगी आग ने आसपास की दूसरी कंपनियों की यूनिटों को भी अपनी चपेट में ले लिया। रातभर दमकलें का गड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं, लेकिन सुबह तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका।

जिस कंपनी में आग लगी, वह वेस्ट मैनेजमेंट और केमिकल चर्चे के निपटान का काम करती है। आग को फैलते देर नहीं लगी और केमिकल से भरे ड्रमों में धमाके होने लगे। उस समय फ़ैक्टरी में दस मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हें समय रहते बाहर



निकाल लिया गया। आग ने पास की रेलवे और डिफेंस सप्लायर कंपनियों के शेड को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। आग बुझाने के लिए धार, इंदौर सहित आसपास के इलाकों से दमकलें की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन सुबह पांच बजे तक आग

पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था। आग की लपटें और धुएँ के काले बादल एक किलोमीटर दूर से नजर आ रहे थे। घटनास्थल के आसपास कोई आबादी क्षेत्र नहीं था, लेकिन वहां मौजूद दुकानों और ढाबों को पुलिस ने बंद करा दिया और संचालकों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा। इंदौर से भी एसडीआरएफ की टीम देर रात पीथमपुर पहुंची और आग बुझाने के कार्य में जुट गई। हजारगो कंपनी में लगी आग की चपेट में स्लीपल्यू इंडिया और गलाइं स्टील लिमिटेड कंपनियों भी आ गईं। आग के कारण दोनों कंपनियों के बड़े प्लांट और मशीनें जल गईं, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है।

ट्रेन में अचानक यात्री को काट खाया चूहा, बहने लगा खून, मचा हड़कंप

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

कुछ महीने पहले एयरपोर्ट पर एक इंजीनियर को चूहे के काटे जाने की घटना के बाद अब ट्रेन में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। महोबा से इंदौर आ रही रीवा-महू एकसेम में एक यात्री को चूहे ने काट लिया, जिससे रेलवे की स्वच्छता और यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ट्रेन क्रमांक 14116 में सफर कर रहे यात्री शिवसहाय वमहोबा से इंदौर के लिए रवाना हुए थे। वे स्लीपर क्लास के एस 4 कोच में सीट नंबर 30 पर यात्रा कर रहे थे। यात्री का आरोप है कि कोच में पहले से ही गंदगी का माहौल था। इसी दौरान अचानक एक चूहा उनके पैर पर चढ़ गया और काट लिया।



घटना के बाद उनके पैर से खून बहने लगा और तेज दर्द के साथ बुखार भी चढ़ गया। पीड़ित यात्री ने रेलवे अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई और दर्द निवारक दवाओं की मांग की। हालांकि आरोप है कि यात्रा के दौरान उन्हें समय पर कोई चिकित्सकीय सहायता नहीं मिल सकी। दर्द और असहजता के बीच उन्हें पूरी यात्रा मजबूरी में पूरी करनी पड़ी। यात्री ने अपनी शिकायत रेल मदद पोर्टल पर भी दर्ज कराई। जवाब में रेलवे की ओर से आश्वासन दिया गया कि शिकायत

संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। वहीं रतलाम मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार चूहे के काटने से संक्रमण और गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। ऐसे मामलों में तुरंत प्राथमिक उपचार और चिकित्सकीय देखभाल बेहद जरूरी होती है। लापरवाही गंभीर हो सकती है, यहां तक कि कुछ मामलों में प्रभावित अंग को नुकसान भी पहुंच सकता है। इस घटना ने एक बार फिर रेलवे की सफाई व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों का कहना है कि नियमित सफाई और निगरानी के दवाव हकीकत में कहीं नजर नहीं आते, जिससे सफर अब सुरक्षित कम और जोखिम भरा ज्यादा महसूस होने लगा है।

शादी में बिन बुलाए मेहमानों ने मचाया हंगामा, घरातियों-बारातियों से की मारपीट

इंदौर ■ ग्लोबल हेराल्ड

मध्यप्रदेश के इंदौर में बीती रात एक शादी के दौरान जमकर हंगामा हुआ। घटना तेजाजी नगर क्षेत्र की है जहां एक शादी समारोह में देर रात उस वक्त हंगामा मच गया जब आपस में विवाद कर रहे कुछ युवक लड़ते-भिड़ते शादी के मंडप में जा घुसे। लड़ रहे युवकों को जब बारातियों व घरातियों ने रोکنे की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ भी डंडों और लात-चूंसों से मारपीट की और मंडप में रखी कुर्सियां-टेबल तोड़ दीं। हमले में एक बुजुर्ग सहित 6 लोग घायल हो गए। हमले के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भागे गए।

थाना तेजाजी नगर पुलिस के मुताबिक घटना कल रात 12.15 बजे ग्राम माचला में हुई। यहां शादी की लड़ते-झगड़ते हुए सीधे मंडप में घुस आए। जब घरातियों ने उन्हें मंडप से दूर जाने को कहा तो आरोपियों ने गालियां देना शुरू कर दीं। उन्होंने लात-चूंसों और डंडे से हमला कर दिया। इससे शादी के मंडप में हड़कंप मच गया। बदमाशों ने मंडप में रखी कुर्सियां-टेबल उठाकर फेंकी और तोड़ दीं।

एक बुजुर्ग सहित 6 लोग घायल

फरियादी जगराम ने पुलिस को बताया कि मारपीट में उसे आंख के पास चोट आई। जबकि 70 वर्षीय समथी लक्ष्मण बंजारा को सिर, चेहरे, हाथ, गर्दन और पीट पर चोट लगी। इसी तरह समथन गंगाबाई को कमर और पीट में चोट आई। लक्ष्मण के बेटे जगदीश को सिर, चेहरे व हाथ, कलाबाई को चेहरे पर और पुरकिया उर्फ प्रेम चौहान को कंधे और कनपटी पर चोट आई। शोर सुनकर अन्य लोग भी बच-बचाव करने आए तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। घायल बुजुर्ग लक्ष्मण की हालत गंभीर बताई गई है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है और पुलिसियों की तलाश में जुट गई है।

खुशियां चीख-पुकार और मातम में बदल गईं। पुलिस ने फरियादी जगराम पिता रतन बंजारा (50) मूल निवासी गोगावां जिला खरगोन की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। फरियादी जगराम ने पुलिस को बताया कि वे ग्राम माचला में मनीषा की शादी में आए थे। मनीषा के फेरो की तैवारी चल रही थी तभी आरोपी आपस में

एमपी में भीषण सड़क हादसा, एक साथ उठी 6 अर्थियां, शादी वाले गांव में पसरा मातम

बड़वानी

बडराजमार्ग पर मौत ने बारात का रास्ता छीन लिया। खरगोन रोड पर टोल प्लाजा के पास बोलेरो और टैकर की आमने-सामने टक्कर में छह युवकों की जान चली गई। बोलेरो एमपी 46 टी 0894 में सात युवक सवार थे। ये सभी राजपुर के पास अतरसंभा गांव से रूई गांव आई बारात में शामिल होने आए थे। इनमें दूल्हे का भाई यशवंत भी था। बताया गया कि युवक रूई से जुलवानिया डीजल भरवाने आए थे। डीजल भरवाकर रूई लौट रहे थे। तभी जुलवानिया और रूई के बीच टोल प्लाजा के पास खरगोन से आ रहे टैकर एमपी 09 बीजी 5750 से बोलेरो भिड़ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए।



सहिते (25) निवासी सालखेड़ा और पहरवपू पिता हीरालाल भिलाला (32) निवासी लिंबाई की मौके पर ही मौत हो गई। दो युवकों के शव बोलेरो में बुरी तरह फंस गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर शवों को निकाला। गंभीर घायल आकाश पिता दयाराम (25) निवासी रालामंडल सिवाई व सोहन पिता झवरसिंह

सचिन पिता गोकुल वास्करले (25) निवासी पटेलपुरा साकड़, प्रद्युगन पिता गुलीचंद

बघेल (28) निवासी सालखेड़ा ने जुलवानिया अस्पताल में दम तोड़ दिया। सुरेश पिता मांगीलाल (28) निवासी देवझिरी, और यशवंत पिता सुपंडिया (30) निवासी अतरसंभा को बड़वानी रेफर किया गया। परिजन यशवंत को निजी वाहन से बड़वानी ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। यशवंत को मिलाकर हादसे में छह लोगों की मौत हो गई।

गांव में पसरा मातम

हादसे की खबर मिलते ही रूई में बारात का माहौल गमगीन हो गया। जुलवानिया अस्पताल में शवों के बीच परिजनों की चीखें गूंज उठीं। शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। शादी को जल्द निपटारकर लोग अर्थी की तैयारियों में जुट गए। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। टैकर जड़त कर चालक की तलाश जारी है।

बंद पड़ी एंबुलेंस

बड़े हादसों के लिए जुलवानिया पॉइंट पर 108 एंबुलेंस तैनात की गई थी। मकसद था कि गंभीर घायलों को गोल्डन ऑवर में इलाज मिले और समय रहते बड़वानी रेफर किया जा सके। पर मंगलवार को जब छह जिंदगियां सांसें से लड़ रही थीं, तब एंबुलेंस सुधार के लिए बंद खड़ी थी। जिम्मेदारों की लापरवाही ने सिस्टम की पोल खोल दी। हाईवे के हादसों को देखते हुए ये एंबुलेंस दी गई थी, लेकिन आज जब जरूरत पड़ी तो, एंबुलेंस को ही इलाज की जरूरत थी। देर से अंजड़ पॉइंट से आई 108 एंबुलेंस दो घायलों को लेकर राजपुर में खराब होकर खड़ी हो गई। इससे पहले यशवंत को परिजन निजी वाहन से बड़वानी ले गए, जिसने रास्ते में दम तोड़ दिया। सवाल उठता है। यदि एंबुलेंस चालू होती तो क्या एक जान नहीं बच जाती?

23 लाख का घोटाला: बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में फर्जी खातों से निकाली रकम एमपी ईओडब्ल्यू ने की 8 कर्मचारियों पर एफआईआर

भोपाल



ने मिलकर ग्राहकों के खातों से अवैध रूप से रकम निकाली। आरोपियों में गौरीशंकर राम, ऋचि तिवारी, इंद्रनाथ विश्वास, विकास शर्मा, विकास त्रिवेदी, विजय कुमार मेहता और सोरभ मिश्रा के नाम शामिल हैं।

फर्जी खातों और दस्तावेजों का खेल जांच में खुलासा हुआ कि

आरोपियों ने ग्राहकों की जानकारी के बिना उनकी आईडी का उपयोग कर फर्जी बचत खाते खोले। इसके अलावा कुछ वास्तविक खातों का भी दुरुपयोग किया गया। आठ खाताधारकों की 11 एफडीआर (फिक्स्ड डिपॉजिट) को समय से पहले बंद कर दिया गया और प्राप्त राशि को फर्जी खातों में ट्रांसफर कर लिया गया। आरोप है कि इस पूरी साजिश के तहत करीब 23,09,450 रुपये की राशि को जाली वाउचरों और फर्जी दस्तावेजों के जरिए निकाल लिया गया। यह रकम खाताधारकों की जानकारी के बिना ट्रांसफर और आहरित की गई।

बिजासन की डबल पुलिया पर ट्रक के उड़े परखच्चे, दो की मौत

बड़वानी



बड़वानी जिले के संधवा के पास मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बिजासन घाट के ब्लैक स्पांट पर ट्रक और ट्रेलर की टक्कर में दो लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जानकारों का अनुसार, बुधवार दोपहर करीब 2 बजे बिजासन घाट के डबल पुलिया के बीच एक तेज रफ्तार ट्रक आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया।

केबिन में फंसे चालक

हादसे के बाद ट्रक में सवार चालक और सहचालक केबिन में बुरी तरह फंस गए। उन्हें बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला जा सका।

मृतकों की पहचान चालक अब्दुल पिता हबीब अंसारी और सहचालक जगन्नाथ पिता मगनजी दंगी निवासी लाहौरिया तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर के रूप में हुई है। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

हादसे की वजह

पुलिस के अनुसार, इंदौर-मुंबई मार्ग पर ट्रेलर (टीएन 88 एम 1053) के घाट उतर रहा था, तभी पीछे से आ रहा ट्रक (एमपी 09 एचएच 8867) उसमें जा चुका। बिजासन चौकी

प्रभारी रोहित पाटीदार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना माना जा रहा है। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे करवाया। पुलिस की सक्रियता के चलते नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित नहीं हुआ और आवाजाही सुचारु बनी रही। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के पीएम रूम में रखवाया है और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त कर मर्ग कायम कर लिया है। मामले की जांच जारी है।

बारात में नाच-गाने के बीच गूंजा ठाय-ठाय, युवक की गई जान, एक घायल

राजगढ़



मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सनसनीखेज मामले ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। ब्यावरा शहर में एक शादी समारोह में की गई एक लापरवाही ने खुशियों को मातम में बदल दिया। यहां एक युवक की लापरवाही ने व्यक्ति की जान ले ली। यही नहीं, एक शख्स बुरी तरह घायल भी हो गया। पुलिस अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज जांच में जुट चुकी है। घटना 21 अप्रैल की रात 1 से 1.10 बजे के बीच की बताई जा रही है।

मामला कुंभराज थाना क्षेत्र के ग्राम घाटाखेड़ी का है। यहां मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात हर्ष फायर के दौरान चली गेली से एक युवक की मौके पर मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। मिली जानकारी के मलावर थाना क्षेत्र के गांव गिंदौरमीणा के रहने वाले राहुल मीणा (28) पिता गजराज मीणा की बारात 21 अप्रैल की रात घाटाखेड़ी

गांव में मजबूतसिंह मीणा की बेटी शिवानी के विवाह के लिए पहुंची थी। रात करीब एक बजे बारात पहुंची। यहां स्वागत के दौरान घर के आंगन में बरात में ही आए एक अज्ञात युवक ने हर्ष फायर कर दिया। फायरिंग के दौरान चली गेली घाटाखेड़ी निवासी घनश्याम मीणा (30) पिता बालकृष्ण मीणा के कंधे के पास लगी। गंभीर चोट के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, घटना में चंदनसिंह मीणा निवासी कानाखेड़ी घायल हो गया। घायल चंदनसिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

गिंदौरमीणा के युवक की लाइसेंस बंदूक से फायर मिली जानकारी के अनुसार, स्थानीय

स्तर पर यह भी चर्चा है कि बारात में शामिल गिंदौरमीणा निवासी श्रवण मीणा द्वारा लाइसेंस 12 बोर बंदूक से हर्ष फायर किया गया था। हालांकि, इस बात की पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और अज्ञात आरोपी के खिलाफ जांच जारी है। टीआई कुंभराज पंजक त्यागी का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है। इस घटना में दुल्हन के गांव घाटाखेड़ी निवासी व्यक्ति की मौत हुई है। वह गांव का ही है और शादी में शामिल होने आया था। वहीं, गिंदौरमीणा से बरात में गए श्रवण मीणा द्वारा हर्ष फायर करने की बात की जा रही है। जो सीधी घनश्याम को जाकर लगी। हालांकि कुंभराज थाना पुलिस ने फरियादी रामजीवन मीणा (36) निवासी घाटाखेड़ी की रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

300 मेहमान करते रहे इंतजार, 1 बजे खुली पोल, बर्बाद होने से बच गई एक बेटी की जिंदगी

दमोह

सिटी कोतवाली क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में सोमवार की रात एक बड़ा फर्जीवाड़ा शादी समारोह के दौरान सामने आया है। गनीमत रही कि लकड़ी पक्ष के लोगों ने थोड़ी समझदारी दिखाई, नतीजन उनकी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से भी बच गई। यह पूरा खेल फेसबुक से शुरू हुआ और अब थाने पहुंच चुका है।

दरअसल, रेलवे इंस्टीट्यूट हॉल में दमोह की रैक्वार् समाज की एक लड़की की शादी शाजापुर के लड़के से होना थी। लड़की पक्ष ने पूरी तैयारियां कर रखी थीं, टेंट सजा था, घोड़ी बग्गी, बाजा वाले सब तैयार थे। न्यौते पर 300 से अधिक लोग भोजन करने भी पहुंचे थे, लेकिन रात 1 बजे तक जब बारात नहीं पहुंची तो, लड़की वालों को संदेह हुआ और

उसके बाद जो खुलासा हुए उसने सभी के होश उड़ा दिए। बारात, वरमाला, फेरे हर चीज की तैयारी थी, लेकिन लड़का मौजूद नहीं था। लड़की वालों ने जब बारात का पृष्ठ तो बस से रात 11 बजे तक आना बताया गया। इसके बाद बारात की बस गढ़ाकोटा में खराब होना बताया और फिर रात 1 बजे तक बहानेबाजी चलती रही। इस बीच जब परिजनों को संदेह हुआ तो, दूल्हा सहित तीनों से सखी से पूछताछ की गई। बाद में पूरा मामला बड़े फ्रांंड से जुड़ा समझ आने लगा और पुलिस बुलाकर तीनों को उनके सुपुर्द किया गया। पूरा फ्रांंड सामने आने के बाद जब परिजनों ने दूल्हा और उसके साथ आए दो लोगों से पूछताछ की, तो दूल्हे ने खुद के अलग-अलग नाम बताए। मही में रेलवे में नौकरी में नहीं होना भी बताया।

30 दिन में फिर शुरू होंगे आरटीओ चेक पोस्ट, सरकार को राहत के साथ सख्त निर्देश

जबलपुर

जबलपुर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरटीओ चेक पोस्ट बंद किए जाने से जुड़े अवमानना मामले का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को 30 दिनों की मोहलत दी है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि तय समय में चेक पोस्ट दोबारा शुरू किए जाएं, अन्यथा अवमानना याचिका फिर से दायर की जा सकेगी। यह मामला सतना निवासी रजनीश त्रिपाठी द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जुबिन प्रसाद ने पक्ष रखा। यह जनहित याचिका वर्ष 2006 में वाहनों की ओवरलोडिंग और सड़क

हादसों को रोकने के उद्देश्य से दायर की गई थी। सरकार ने वर्ष 2023 में हलफनामे के जरिए आश्वासन दिया था कि राज्य में चेक पोस्ट चालू रहेंगे और ओवरलोडिंग रोकने के लिए अन्य उपाय भी किए जाएंगे। लेकिन इसके बाद 30 जून 2024 से आरटीओ चेक पोस्ट बंद कर दिए गए, जिसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद सरकार को 30 दिनों के भीतर चेक पोस्ट फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार पहले दो गई अंडरटेकिंग का पालन करे और चेक पोस्टों का संचालन बहाल करे।

मेट्रो के लिए चाहिए 80 एकड़ जमीन तत्काल आदेश जारी, भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेज

भोपाल



भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 80 एकड़ जमीन तुरंत चाहिए। इसके लिए कलेक्टर प्रियंका मिश्रा तत्काल आदेश जारी करते हुए एक्सचेंज स्टेशन के लिए आरा मशीनों को शिफ्ट करने को कहा है। साथ ही भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरणों को तेजी से निपटार करने के भी निर्देश दिए। धारा 19 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने एमआइडीसी, वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि मेट्रो निर्माण से प्रभावित आरा मशीनों के स्थानांतरण की कार्रवाई

जल्द पूरी करें। सभी एएसडीएम को मिशन मोड में काम करने का कहा गया। उन्होंने चिन्हित भूमि का सीमांकन कर कंपनी को सौंपने के भी निर्देश दिए। जहां कहीं मेट्रो में भूमि संबंधी विवाद उत्पन्न हो, वहां प्रकरण को कलेक्टर के संज्ञान में लाकर उसका त्वरित समाधान करने का कहा है। उन्होंने

कहा कि जिन स्थानों पर भूमि संबंधी कोई विवाद नहीं है, वहां मेट्रो कंपनी काम शुरू करे।

ऑरेंज लाइन का चल रहा काम

गौरतलब है कि भोपाल मेट्रो परियोजना के अंतर्गत ऑरेंज लाइन (प्रायोरिटी कॉरिडोर) सुभाष नगर से केन्द्रीय विद्यालय बोर्ड ऑफिस चौराहा होते हुए एम्स तक विकसित की जा रही है। इसके अतिरिक्त ब्लू लाइन रूट भद्रबाद डिपो चौराहा, जवाहर चौक, रोशनपुरा, कुशाभाऊ उदयन हो, वहां प्रकरण को कलेक्टर के संज्ञान में लाकर उसका त्वरित समाधान करने का कहा है। उन्होंने

पिपलानी और रत्नागिरी तिराहा तक प्रस्तावित है। बैठक में अपर कलेक्टर सुमित पांडे, मेट्रो मंडल प्रबंधक, नगर निगम के अपर आयुक्त सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं एसडीएम उपस्थित थे।

3.36 किमी की अंडरग्राउंड लाइन

वहीं दूसरी ओर मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत 3.36 किमी लंबाई की अंडरग्राउंड लाइन बनाना तय है। ऐशबाग से डीआइजी बंगला, सिंधी कॉलोनी तक भोपाल स्टेशन व नादरा बस स्टैंड होते हुए काम होगा। इसे पूरा करने शुरूआत में तीन से चार माह का लक्ष्य तय किया था।

महिला की जांच रिपोर्ट देख कर दिया पुरुष का इलाज, मौत

ग्वालियर



अंचल के सबसे बड़े जया आरोग्य अस्पताल (जेएचएच) में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुरुष मरीज का इलाज किसी महिला की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कर दिया गया। गलत रिपोर्ट और गलत इलाज से मरीज की मौत हो गई।

यह आरोप लगाते हुए मरीज की बेटी ने गजराजा मेडिकल कॉलेज डीन से शिकायत कर जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार को मदद देने भी बात कही। गुड्डा की रागिनी जाधव ने डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ से शिकायत की है। पिता दिलीप राव को घबराहट होने पर 18 अप्रैल को रागिनी जाधव ने दोपहर 2.30

बजे जेएच में भर्ती कराया था। अस्पताल की लैब से मिली रिपोर्ट में दिलीप के बजाय पुष्पा नामक महिला का नाम था। परिजन ने नावा किया, डॉक्टरों ने इसे दरअंतरांज कर सीरी रिपोर्ट के आधार पर इलाज कर दिया। डीन डॉ. आरकेएस धाकड़ कहा, मामला गंभीर है। रिपोर्ट पर नाम गलत होने के बाद इलाज कैसे किया गया। जांच के लिए समिति बनेगी। दोषी पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

वैलथ क्रिएशन के अचूक 'थंब रूल्स' जो महंगाई के चक्रव्यूह को भेदकर खड़ी करेंगे आपकी आर्थिक सल्लतनत

क्या आप जानते हैं कि आपके बैंक खाते में बढ़ता हुआ बैलेंस कभी-कभी एक 'खुबसूरत वित्तीय छलावा' भी हो सकता है?

अधिकतर निवेशक इस भ्रम में जी रहे हैं कि उनका पैसा बढ़ रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि वे एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जहाँ रफ्तार तो बहुत है, लेकिन रास्ता कभी भी तय न होता है। आज के दौर में असल रईस वह नहीं है जो सिर्फ निवेश करता है, बल्कि वह है जो समय, लागत, टैक्स और महंगाई के उस चतुर्भुज जाल को भेदना जानता है जो चुपचाप आपकी मेहनत की कमाई को लील रहा है।

अगर आप भी इस जटिल वित्तीय चक्रव्यूह से निकलकर एक ऐसी 'ऑटोमेटेड मनी मशीन' खड़ी करना चाहते हैं जो आपके सोते समय भी आपके लिए दौलत का सृजन करे, तो आपको निवेश के इन १० ट्राइड एन्ड टेस्टेड सक्सेस मेट्रिक्स को अपने पोर्टफोलियो में आज और अभी शामिल करना चाहिए।

1. रूल ऑफ 70: महंगाई का अहश्य दीमक- यह नियम बताता है कि महंगाई आपके पैसे की खरीदने की शक्ति को कितने समय में आधा कर देगी। उदाहरण के तौर पर, यदि महंगाई दर 7% है, तो 70 को 7 से भाग

देने पर 10 आता है। यानी आज जो कार 10 लाख की है, 10 साल बाद वह 20 लाख की होगी। हानि: यदि आप अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट (3% ब्याज) में रखते हैं, तो आपका पैसा महंगाई से हार रहा है। 10 साल बाद आपके पास पैसे तो होंगे, लेकिन आप उनसे आधा सामान भी नहीं खरीद पाएंगे। यह आपकी 'पर्चैजिंग पावर' की सीधी हत्या है।

2. इन्व्स्टमेंट डबल करने टाइम थंब रूल: 72, 114 और 144 - ये नियम आपको बताते हैं कि अलग-अलग लक्ष्यों के लिए आपको कितना समय चाहिए। रूल ऑफ 72 (दोगुना) के तहत यदि आप 12% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो 6 साल में पैसा दोगुना होगा। रूल ऑफ 114 (तिगुना) के अनुसार उसी 12% पर 9.5 साल में पैसा तीन गुना होगा, जबकि रूल ऑफ 144 (चौगुना) के अनुसार 12 साल लगेगे। हानि: इन नियमों की जानकारी न होने पर निवेशक गलत लक्ष्य तय करते हैं। यदि आप 7% वाली ऋद्ध में पैसा तिगुना करने की सोच रहे हैं, तो आपको 16 साल से ज्यादा लगेगे। समय का सही आकलन न होना आपके वित्तीय भविष्य को असुरक्षित बना देता है।

3. रूल ऑफ 69: सटीकता का पैमाना - यह नियम उन फंड्स के लिए है जहाँ पैसा हर रोज या हर महीने कंपाउंड होता है (जैसे म्यूचुअल फंड ग्रोथ स्क्रीमें)। उदाहरण के लिए, 69 को ब्याज दर से भाग देकर उसमें 0.35 जोड़ें। यह 'रूल ऑफ 72' से अधिक सटीक परिणाम देता है। हानि: प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए 0.5% का अंतर भी करोड़ों का होता है। इस सटीकता की कमी से बड़े निवेशक अपने 'एग्जिट प्लान' में बड़ी चूक कर सकते हैं।



4. 100 माइंस उम्र का सिद्धांत: एसेट एलोकेशन - यह तय करता है कि जोखिम और सुरक्षा का अनुपात क्या हो। उदाहरण के तौर पर, यदि उम्र 30 वर्ष है, तो 100 - 30 = 70% पैसा शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। हानि: यदि कोई युवा 30 की उम्र में सारा पैसा सिर्फ एफडी या गोल्ड में रखता है, तो वह 'अपर्च्युनिटी कॉस्ट' खो रहा है। वह कंपाउंडिंग की उम्र शक्ति का लाभ नहीं उठा पाता जो उसे रिटायरमेंट तक करोड़पति बना सकती थी।

5. लागत प्रबंधन: एक्सपेंस रेशियो का खेल - निवेश में 'फीस' चुपके से आपका मुनाफा खा जाती है। उदाहरण के लिए, एक फंड 15% फीस लेता है और दूसरा 0.5%। सुनने में यह 1% मामूली लगता है, लेकिन 30 साल के निवेश में यह आपकी कुल मैच्योरिटी वैल्यू का 30% हिस्सा कम कर सकता है। हानि: अज्ञानता में 'रिगुलर प्लान' चुनना आपके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा एजेंटों

के कमीशन में बांट देता है। हमेशा 'Direct' फंड्स को प्राथमिकता देना ही समझदारी है।

6. वित्तीय अनुशासन: 50-30-20 और 40% ईएमआई नियम - यह आपके कैश फ्लो को नियंत्रित करता है। 50% जरूरत, 30% इच्छा और 20% अनिवार्य निवेश का संतुलन बनाएँ। साथ ही, आपकी सभी किश्तें (ईएमआई) आय के 40% से अधिक न हों। हानि: यदि ईएमआई 40% से ऊपर जाती है, तो आप 'डेट ट्रेप' (कर्ज के जाल) में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में एक भी महीने की आय रुकने पर आपका पूरा निवेश पोर्टफोलियो बिखर सकता है।

7. रूल ऑफ 15-15-15: करोड़पति बनने का ब्लूप्रिंट - यह नियम विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। यदि आप 15,000 प्रति माह की SIP, 15 साल तक करते हैं और आरंभिक 15% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो 15 साल बाद आपके पास 1 करोड़ का फंड होगा। हानि: इस अनुशासन की कमी का मतलब है कि आप कंपाउंडिंग के 'मैजिक कर्व' तक कभी पहुँच ही नहीं पाते। अधिकांश लोग 5-6 साल में निवेश रोक देते हैं, जिससे वे उस विशाल धन से वंचित रह जाते हैं जो निवेश के अंतिम वर्षों में सृजित होता है।

8. रूल ऑफ 25: रिटायरमेंट का मैजिक नंबर - यह नियम बताता है कि आपको काम छोड़ने के लिए कुल कितने पैसे की जरूरत है। आपका कुल संचित कोष आपके वर्तमान वार्षिक खर्च का कम से कम 25 गुना होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका सालाना खर्च ₹10 लाख है, तो आपको रिटायर होने के लिए

₹2.5 करोड़ की जरूरत है। हानि: इस गणना के बिना रिटायर होना एक 'वित्तीय आत्महत्या' जैसा है। बिना स्पष्ट लक्ष्य के निवेश करने वाले लोग अक्सर रिटायरमेंट के कुछ वर्षों बाद ही पैसे की तंगी का सामना करने लगते हैं।

9. 4% विड्रॉल नियम: सस्टेनेबल इनकम - यह रिटायरमेंट के बाद पैसा निकालने का सुरक्षित पैमाना है। रिटायरमेंट के बाद, अपने कुल फंड का केवल 4% हिस्सा ही प्रति वर्ष खर्च के लिए निकालें। इससे आपका मूल धन सुरक्षित रहेगा और महंगाई के बावजूद आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। हानि: जो लोग रिटायरमेंट फंड से अनियंत्रित पैसा निकालते हैं, वे अक्सर 'सीवेंस ऑफ रिटर्न रिस्क' का शिकार हो जाते हैं और उनका फंड समय से पहले समाप्त हो सकता है।

10. रूल ऑफ 5%: पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन - यह नियम आपको किसी एक जगह बड़ा नुकसान होने से बचाता है। आपके कुल निवेश का 5% से अधिक हिस्सा किसी एक कंपनी के शेयर या एक ही सेक्टर के फंड में नहीं होना चाहिए। हानि: अक्सर निवेशक 'एक ही टोकरी में सारे अंडे' रखने की गलती करते हैं। यदि वह विशेष सेक्टर या कंपनी संकट में आती है, तो निवेशक का पूरा पोर्टफोलियो तबाह हो जाता है।

यदि आपने सोते समय पैसा कमाने का रास्ता नहीं ढूँढा, तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। असली रईस वह नहीं है जो सिर्फ ज्यादा कमाता है, बल्कि वह है जो इन नियमों के जरिए अपने पैसे को एक 'मनी मशीन' में बदल देता है।

(नोट: इस लेख में ये दिए गए विचार लेखक के अपने विचार हैं)

एमपी हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री पर लगाई रोक, यथास्थिति पर उप पंजीयकों को सर्कुलर जारी करने के लिए निर्देश

ग्वालियर ■

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्टे के बावजूद रजिस्ट्री पर सख्त रुख दिखाया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एमपी रजिस्ट्री पर रोक लगाई है। भिंड के एक प्रकरण में याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए। कोर्ट की एकल पीठ ने न्यायालय के 'यथास्थिति' आदेश के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने पंजीयन महानिरीक्षक को निर्देश दिए हैं कि एक माह के भीतर सभी उप पंजीयकों को सर्कुलर जारी कर स्पष्ट करें कि जिन संपत्तियों पर न्यायालय की रोक हो, वहां रजिस्ट्री न की जाए और ऐसे प्रकरण लंबित रखे जाएं।

कोर्ट ने कहा है कि यदि संबंधित जमीन का नामांतरण हो चुका है, तो उसे तत्काल निरस्त किया जाए। इसके लिए भिंड कलेक्टर को

निर्देश दिए गए हैं। मामले में याचिकाकर्ता जितेंद्र गुप्ता ने बताया, भिंड जिले के फूफ क्षेत्र में स्थित विवादित जमीन पर 7 फरवरी 2023 को हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद 10 फरवरी को संबंधित पक्ष आशा प्रिया ने जमीन की रजिस्ट्री करा दी। सुनवाई के दौरान महिला दो वर्ष तक पेश नहीं हुई। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश कर सकी, जहां उसने अंततः माफ़ी मांग ली।

झूठे हलफनामे पर जुमाना

मामले में झूठा हलफनामा देने पर महिला के समुर जगदीश चंद्र पर भी 25 हजार रुपए का जुमाना लगाया गया है। उन्होंने कोर्ट में गलत जानकारी दी थी कि आशा प्रिया पेशी पर नहीं आई थीं, जबकि साक्ष्यों से यह गलत साबित हुआ। उम्र को देखते हुए कोर्ट ने नरमी बरतते



हुए जुमाना जमा करने पर राहत प्रदान की।

सजा की जगह सेवा का विकल्प

कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए महिला को शर्तों के साथ राहत दी है। उसे 15 मई 2026 तक खरीदार को राशि लौटाकर रजिस्ट्री निरस्त करानी होगी। साथ ही, अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए 2 लाख रुपए जमा कर 5 वाटर कूलर और 5 वाटर थ्यूरीफायर कोर्ट परिसर में लगवाने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- स्टे के बावजूद रजिस्ट्री पर हाईकोर्ट सख्त
- 7 फरवरी 2023 को हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
- संपत्ति को यथास्थिति में रखने को कहा
- आदेश के तीन दिन बाद बेच दी थी जमीन
- हाईकोर्ट ने ऐसे मामले में रजिस्ट्री पर रोक लगाई
- उप पंजीयकों को सर्कुलर जारी करने के निर्देश
- लापरवाही पर सिटी प्लानर व भवन अधिकारी को नोटिस।
- इधर ग्वालियर नगर निगम आनुक संघ प्रिय ने एबीपीएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर सहायक नगर निवेशक महेंद्र अग्रवाल और भवन अधिकारी रांकेश कश्यप को कारण बताओ नोटिस जारी किया। निगम ने स्पष्ट किया कि नागरिक शिकायतों के समाधान में देरी बर्दाश्त नहीं होगी।

महानगरों की तर्ज पर बनना है अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, लैंडयूज न बदलने से अटका आइएसबीटी

कटनी ■

शहरवासियों और बस यात्रियों को जल्द ही राहत दिलाने के लिए महानगरों की तर्ज पर पुरेनी में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का निर्माण कराया जाना है। 2017 में हुई मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अबतक यह योजना शहर में मूर्त रूप नहीं ले पाई है।

यह परियोजना परिवहन विभाग और प्रशासन के अधीन थी, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी नगर निगम को सौंप दी गई है। नगर निगम द्वारा इस योजना पर एकदम सुस्त गति से काम किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा 3 जुलाई को ट्रंसपोर्ट नगर के समीप 6 हेक्टेयर से अधिक भूमि भी इसके लिए आवंटित कर दी गई है। भूमि आवंटन के बाद नगर निगम द्वारा शहर में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड



(आईएसबीटी) बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, लेकिन सुस्ती समस्या है। बस स्टैंड का निर्माण शीघ्र हो, इसको लेकर नगर निगम के अफसर व जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। नए आईएसबीटी में एक साथ लगभग 300 से 350 बसों के खड़े होने और संचालन की व्यवस्था होगी, जिससे शहर में बस परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। वर्तमान में शहर का प्रिवदर्शनी बस स्टैंड प्रतिदिन करीब 220 बसों के संचालन का भार संभाल रहा है, लेकिन यहां जगह और सुविधाओं की कमी के चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

जबलपुर में खौफनाक हिट एंड रन: पानी लेने रुके थे, कार ने ली 2 की जान

जबलपुर ■

मध्यप्रदेश के जबलपुर में एक कार चालक ने तीन लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्यप्रदेश के जबलपुर में बुधवार को सुबह यह वारदात हुई है। कार चालक नशे की हालत में था और कार को तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक यह घटना मंगलवार और बुधवार को दरमियानी रात हुई। गढ़ा पुलिस थाना क्षेत्र में धनवंतरी नगर चौक के पास यह घटना हुई।

नगर पुलिस अधीक्षक आशीष जैन ने मीडिया को बताया कि गणेश प्रसाद कुशवाह (38) और उनके बेटे शुभम (15) एक शादी में



शामिल होने के लिए एक इलाके में आए थे। जब वे अपने गृह नगर महाराजपुर लौट रहे थे, तभी पानी खरीदने के लिए एक दुकान के सामने मोटरसाइकिल से रुक गए। पुलिस के मुताबिक पिता और पुत्र जब अपनी बाइक के पास खड़े थे, तभी वहां पर तेज रफ्तार कार आई और सड़क किनारे खड़े पिता-पुत्र को टक्कर मार दी। साथ ही पंकज साहू (30) को भी टक्कर मार दी। पंकज भी अपनी दोपहिया वाहन के साथ उसी जगह

पर रुका हुआ था। घटना के बाद वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तीनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टरों ने पंकज और गोपाल को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शुभम की हालत गंभीर है। उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक कार चालक रंजी इलाके का रहने वाला है और उसे पकड़ लिया गया है। मेडिकल जांच कराई गई है, जिसकी

भोपाल से गुजरने वाली 24 ट्रेनों को किया डायवर्ट

भोपाल ■

भोपाल रेलवे स्टेशन पर समर सीजन का असर साफ नजर आ रहा है। जहां प्लेटफार्म पर यात्रियों की गहमागहमी बनी रहती है वहीं सभी ट्रेनें खचाखच भरी आ रही हैं। समर सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है पर इसके बावजूद दिक्कत कम नहीं हुई। रेलवे के मेटेनेंस ने यात्रियों को मिलने वाली राहत को घटा दिया है। एक बार फिर रेलवे मेटेनेंस के चलते भोपाल से गुजरने वाली कई ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है। इससे यात्रियों की परेशानी खासी बढ़ गई है। भोपाल रेल मंडल के अधिकारियों के मुताबिक, मेटेनेंस के चलते भोपाल से गुजरने वाली 24 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है।

शादी का कार्ड देने आए, पैर छुए और महिला के सिर में गोली मारी

शिवपुरी ■



मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलास के तेंदुआ थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। थाना क्षेत्र के डेहरवारा गांव में रहने वाली एक महिला की बुधवार दोपहर को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया जो शादी का कार्ड देने के बहाने घर पर आए थे, आरोपियों के दरवाजा खटखटाने पर जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला तो आरोपियों ने महिला के पैर छुए और फिर उसके सिर में गोली मारकर फरार हो गए। घटना के वक्त महिला के साथ घर में उसकी नातिन भी घर पर थी। परिजनों की मांने तो मामला जमीनी रंजिश से जुड़ा हुआ है और इस पूरे हत्याकांड में किसी परिचित का हाथ हो सकता है। ग्राम डेहरवारा निवासी रामसखी

धाकड़ (65 वर्ष) बुधवार को अपने मकान में थी, घर में उसके साथ उसकी बहू और नातिन भी थीं। दोपहर करीब तीन बजे बाइक सवार तीन युवक आए और शादी का कार्ड देने की बात कहकर दरवाजा खुलवाया। जैसे ही रामसखी बाहर आई तो एक युवक ने उसके पैर छुए और तुरंत सिर में कट्टे से गोली मार दी। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गए। घटना इतनी जल्द हुई कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। मौके पर मौजूद वृद्धा की नातिन राधिका धाकड़ मौजूद थीं, जिसने पूरी वारदात देखी और गोली चलने के बाद घर के अन्य लोग भागकर मौके पर आए।

महिला ने की थी दूसरी शादी

परिजनों ने बताया कि रामसखी को दो शादियां हुई थीं और अभी वह अपने दूसरे पति लक्ष्मीनारायण धाकड़ के साथ रह रही थीं। लक्ष्मी नारायण की पहली पत्नी से तीन बेटे और दो बेटियां थीं, जबकि रामसखी अपने पहले पति से जन्मे बेटे मुनेश को अपने साथ लाई थीं। रामसखी की लक्ष्मीनारायण से कोई संतान नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सभी बच्चों का पालन-पोषण किया। वर्तमान में मुनेश धाकड़ इंदौर में अपने परिवार के साथ रहता है और हाल ही में अपनी मां के इलाज के लिए गांव आया था। इस पूरे घटनाक्रम में मुताबिक के भाई महेश धाकड़ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लक्ष्मी नारायण के नाम को करीब 35 बीघा जमीन का बंटवारा हो चुका था, जिसमें रामसखी अपने हिस्से की जमीन बेटे मुनेश के नाम करवाना चाहती थीं और इसकी प्रक्रिया भी चल रही थी। पर रामसखी के सौतेले बेटे शिवराज धाकड़, साहब सिंह धाकड़ व रामकृष्ण धाकड़ जमीनी मुनेश के नाम करने के विरोध में थे।

पुत्र मोह में आईपीएस से भिड़ने वाले बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी को पार्टी ने दिया नोटिस

शिवपुरी ■

मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रीतम लोधी के द्वारा करैरा एसडीओपी डॉ. आयुष जाखड़ को धमकाने के मामले में आईपीएस एसोसिएशन के मैदान में उतरने के एक दिन बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन्हें नोटिस जारी किया है। बता दें कि आईपीएस एसोसिएशन ने पत्र लिखकर विधायक प्रीतम लोधी की भाषा को अशोभनीय और अमर्यादित बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। प्रीतम लोधी को पार्टी ने दिया नोटिस पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी के द्वारा लगातार की जा रही बयानबाजी पर एक तरफ जहां प्रदेश की सियासत गर्माई हुई है वहीं दूसरी



तरफ अब प्रीतम लोधी की बयानबाजी से बीजेपी आलाकमान भी नाराज नजर आ रहा है। मध्यप्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रीतम लोधी को नोटिस जारी किया है नोटिस में लिखा है- विवाद दिनों आपके द्वारा जो आचरण किया गया है वो अत्यंत आपत्तिजनक है। आपके द्वारा किया गया आचरण पार्टी के अनुशासन के अनुरूप नहीं है, अतः तीन दिन के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें अन्यथा आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

लोधी ने एसडीओपी को दी है धमकी

बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के एक के बाद एक तीन वीडियो सामने आए हैं जिनमें वो एसडीओपी को धमकाते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में धमकाते हुए कह रहे हैं कि करैरा क्या तुम्हारे डैडी का है जबकि दूसरे में कह रहे हैं कि, 'मेरा हाथ पहले ढाई किलो का था, लेकिन अब ढाई सौ किलो का हो गया है, इसकी (एसपी, एसडीओपी) बेचैनी दूर कर दूंगा।' प्रीतम लोधी वहीं नहीं रुके उन्होंने आगे ये भी कहा कि, '110 हजार लोगों को ले जाकर एसडीओपी के बंगले को गोबर से भर दूंगा।' साथ ही, उन्होंने शिवपुरी एसपी से स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा कि, बताएं दिल्ली से इनको कौन चला रहा है? कौन प्रमाण दे रहा है, मोदी, अमितशाह वा सिंघानिया? उन्होंने नए वीडियो में शिवपुरी पुलिस को भी 15 दिन की खुली चुनौती दी है।

आस्था से खिलवाड़ बंद करो! शास्त्री

छतरपुर/प्रयागराज ■

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में चल रही हनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक चश्मा बनाने वाली कंपनी के कथित ड्रेस कोड को लेकर सख्त बयान दिया। उन्होंने धार्मिक प्रतीकों पर कथित रोक को लेकर नाराजगी जताई और हिंदू समाज से एकजुट रहने की अपील की। उनकी कथा 21 से 23 अप्रैल तक जारी रहेगी।

ड्रेस कोड को लेकर विवाद

विवाद की वजह एक चश्मा बनाने वाली कंपनी द्वारा कर्मचारियों के लिए बनाए गए कथित ड्रेस कोड को बताया जा रहा है, जिसमें तिलक, सिंदूर और मंगलसूत्र जैसे धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाने की बात सामने आई है।



कथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे तिलक, सिंदूर और मंगलसूत्र लगाकर काम पर नहीं आ सकते। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जो लोग धार्मिक पहचान से परेशानी रखते हैं, उन्हें भारत में रहने के बजाय कहीं और चले जाना चाहिए।

भारत और आस्था पर टिप्पणी

उन्होंने आगे कहा कि भारत में रहने वाले लोग अगर तिलक, चंदन,

राम और हनुमान से दिक्कत रखते हैं, तो उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत किसी एक का नहीं है, यह सभी का है और आस्था के खिलाफ नियम स्वीकार नहीं किए जा सकते।

कंपनी को चेतावनी- धीरेंद्र शास्त्री ने संबंधित कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी समय है अपने फैसले पर पुनर्विचार कर लें, नहीं तो कानून अपना काम करेगा और सरकार कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की और कहा कि अगर आज तिलक और मंगलसूत्र पर सवाल उठ रहे हैं, तो कल सनातन परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों पर भी सवाल उठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे संगम में तीन नदियां मिलकर एक हो जाती हैं, वैसे ही समाज को जातियों से ऊपर उठकर एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए।

कटनी-मुड़वारा के बीच 100 साल पुरानी डायमंड क्रॉसिंग बदली

कटनी ■

कटनी से मुड़वारा के बीच रेलवे ने एक बड़ा तकनीकी बदलाव करते हुए करीब 100 साल पुरानी डबल डायमंड क्रॉसिंग को बदल दिया है। अग्रजों के दौर की इस पुरानी प्रणाली को हटाकर हाल ही में आधुनिक ट्रेक सिस्टम लगाया गया है, जिससे अब ट्रेनों की रफ्तार में इजाफा होगा और यात्रियों को समय की बचत के साथ बेहतर सुविधा मिलेगी।

जानकारी के अनुसार ए केबिन के पास स्थित यह डायमंड क्रॉसिंग लंबे समय से तकनीकी समस्याओं का कारण बनी हुई थी। पुराने सिस्टम के उपकरण न केवल जटिल थे, बल्कि इनके पाटर्स भी आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे। इसके चलते मेटेनेंस में देरी होती थी और हर माह



सुधार कार्य के कारण ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब ट्रेनों की गति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पहले जहां इस सेक्शन पर ट्रेनें करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरती थीं, वहीं अब यह गति बढ़कर 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि कर्व (घुमावदार ट्रेक) पर भी अब ट्रेनें अधिक सहज और तेज गति से गुजर सकेंगी। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए रेलवे को लगभग चार महीने का समय लगा। आवश्यक पाटर्स

लुधियाना और ग्वालियर से मंगवाए गए, जिसके बाद तकनीकी टीम ने पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। क्रॉसिंग बदलने के साथ ही इस हिस्से में नई पटरियां भी बिछाई गई हैं। पहले यहां 52 किलो प्रति मीटर की रेल लाइन थी, जिसे अब 60 किलो प्रति मीटर की मजबूत रेल लाइन से बदल दिया गया है। इससे ट्रेक की लोड क्षमता बढ़ी है और भारी ट्रेनों का संचालन भी अधिक सुरक्षित और सुचारू हो सकेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पुराने डायमंड क्रॉसिंग सिस्टम के कारण प्रक्रिया में शामिल किया गया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद पूरी तरह प्रोसेस किए गए ट्रेकिंग भुगतान किए जाएंगे। जानकारों का मानना है कि ट्रेम प्रशासन द्वारा जिस तरह से प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, उससे भुगतान में देरी होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि जिन कंपनियों ने अतिरिक्त ट्रेकिंग का बोझ ग्राहकों पर डाला था, उनके खिलाफ भी ग्राहक अदालत पहुंचें हैं। इन कंपनियों को अब ग्राहकों को भी पैसा लौटाना पड़ सकता है, अन्यथा वे कानूनी विवाद में फंस सकती हैं। दूसरी ओर रिफंड के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए स्थिति अभी

टैरिफ रिफंड की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन ट्रम्प पैसे दें तब सच में राहत

दुनियाभर के देशों से आने वाले सामान और व्यापार पर अरबों डालर का टैरिफ वसूलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को अब अतिरिक्त वसुली गई राशि वापस करनी पड़ेगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका ने रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन व्यापारियों ने महीनों तक इंतजार किया है, उन्हें अब न्याय मिलने की संभावना है। ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण जिन कंपनियों ने इम्पोर्ट ड्यूटी चुकाई थी, उन्हें अब रिफंड दिया जाएगा। जानकारों के अनुसार अमेरिकी सिस्टम ने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इसके लिए बनाए गए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन



सोहा सिंह लेखक

और आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, इस पोर्टल पर चल रही गतिविधियों को देखते हुए लगता है कि रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी जटिल, चरणबद्ध और लंबी हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण 5.3 करोड़ शिपमेंट पर 166 अरब डालर का टैरिफ वसूला गया था। अब इन सभी का हिसाब करके रिफंड दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 20 फरवरी, 2025 से ट्रम्प प्रशासन द्वारा नए टैरिफ लागू किए गए थे। इसके खिलाफ अमेरिकी अदालत में याचिका दायर की गई थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रम्प सरकार के खिलाफ 6-3 के बहुमत से फैसला दिया गया। ट्रम्प सरकार को

आदेश दिया गया कि वसूला गया टैरिफ गैरकानूनी है और उसे वापस किया जाए। इस मामले में संवैधानिक विवाद के बाद ट्रम्प प्रशासन ने दावा किया था कि 1977 के इमरजेंसी पावर्स कानून के तहत टैरिफ लगाए गए थे, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और टैरिफ वापस करने का आदेश दिया। जानकारों के अनुसार यूएस कस्टम्स एंड बाउंड प्रोटेक्शन ने एक डिजिटल प्रेमवर्क तैयार किया है, जिसके माध्यम से टैरिफ रिफंड की प्रक्रिया शुरू की गई है। कंसोलिटेड एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग आफ एंटीज द्वारा ऑटोमेटेड कमर्शियल एक्वायरनमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आयातक और अधिकृत ब्रोकर अपने क्लेम दर्ज कर सकते हैं। वे अपने शिपमेंट और टैरिफ भुगतान के संबंध में दावे प्रस्तुत कर सकते हैं और सुनवाई में भाग ले सकते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से पिछले एक वर्ष में जिनसे टैरिफ लिया गया है, उनका अर्जियों का चरणबद्ध निपटारा किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन कंपनियों को अतिरिक्त टैरिफ का दावा करना है, उन्हें पहले सीबीपी में नामांकन करना होगा। इसके बाद उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा। एंजेंसी द्वारा इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी और आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी जारी की गई है। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ खाता खोलकर दावा प्रस्तुत करना होगा। एक बार दावा पंजीकृत और स्वीकृत हो जाने के बाद 60 से 90 दिनों के भीतर रिफंड दिया जाएगा। जानकारों के अनुसार अमेरिकी इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में दावों का विवरण सामने आया और दावों की राशि भी ऐतिहासिक रूप से बढ़ी होगी। सीबीपी फाइलिंग्स के अनुसार 3,30,000 से अधिक आयातकों ने असंवैधानिक टैरिफ चुकाया है। अनुमान है कि 5.30 करोड़ से अधिक शिपमेंट के लिए 166 अरब डालर से



अधिक की राशि वापस करनी होगी। वैश्विक स्तर पर फैली मल्टीनेशनल कंपनियों से लेकर छोटे और मध्यम व्यापार से जुड़ी कंपनियों भी इस विशाल दावे में शामिल होंगी। इसके कारण संघीय तंत्र को व्यापक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन आयातकों और ब्रोकरों ने आनलाइन पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करके रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है, उनके दावों की फाइल तैयार हो चुकी है। अनुमान है कि इन दावों की राशि अभी से 127 अरब डालर तक पहुंच गई है। अप्रैल के मध्य तक लगभग 57,000 आयातकों ने पंजीकरण कर लिया था और वे पहले चरण के भुगतान के दावेदार बन चुके हैं। जानकारों के अनुसार यदि इसमें ब्याज जोड़ने का आदेश भी दिया गया, तो कुल भुगतान राशि और अधिक बढ़ सकती है। इस राशि से छोटी कंपनियों और आयातकों को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। ट्रम्प प्रशासन ने रिफंड भुगतान चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय

लिया है। जिन लोगों का पंजीकरण पूरा हो चुका है और जिन्होंने हाल ही में टैरिफ भुगतान किया है, उन्हें पहले चरण में शामिल किया गया है। जिनका पंजीकरण और दस्तावेज सत्यापन जारी है, उन्हें दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। जिन मामलों में अनुमानित ड्यूटी लगाई गई है और जिन्हें 80 दिनों के भीतर फाइलिंग प्रक्रिया में शामिल किया गया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद पूरी तरह प्रोसेस किए गए टैरिफ भुगतान किए जाएंगे। जानकारों का मानना है कि ट्रम्प प्रशासन द्वारा जिस तरह से प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, उससे भुगतान में देरी होने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि जिन कंपनियों ने अतिरिक्त ट्रेकिंग का बोझ ग्राहकों पर डाला था, उनके खिलाफ भी ग्राहक अदालत पहुंचें हैं। इन कंपनियों को अब ग्राहकों को भी पैसा लौटाना पड़ सकता है, अन्यथा वे कानूनी विवाद में फंस सकती हैं। दूसरी ओर रिफंड के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के लिए स्थिति अभी

भी अनिश्चित बनी हुई है। एक तरफ रिफंड मिलने से उनका कैश फ्लो सुधरेगा और वे पुनर्विचार कर सकेंगी, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों के साथ भी उन्हें समायोजन करना होगा। जानकारों का मानना है कि सीपीईए पोर्टल के माध्यम से चल रही प्रक्रिया लंबी और जटिल है। कुछ लोगों का दावा है कि पहले चरण में भी पूरा भुगतान नहीं किया जाएगा और कम से कम भुगतान करने के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रम्प प्रशासन इस भुगतान में लंबा समय ले सकता है और देरी की संभावना बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद कई कारणों से भुगतान में देरी हो सकती है। सिस्टम की क्षमता से अधिक आवेदन, तकनीकी त्रुटियां, दस्तावेज सत्यापन, पात्रता जांच और विवाद निपटान जैसी प्रक्रियाएं समय लेगीं। अधिकारियों का भी मानना है कि 60 से 90 दिन की निर्धारित अवधि से अधिक समय लग सकता है। कुछ मामलों में अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग भी की जा सकती है। इसके अलावा यह संभावना भी जताई जा रही है कि ट्रम्प प्रशासन इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट या इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, जिससे भुगतान और भी देर से हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार दावों और दस्तावेजों की जांच में कम से कम एक वर्ष का समय लग सकता है और बिना जांच के भुगतान संभव नहीं होगा। दूसरी ओर यह भी एक बड़ा सवाल है कि जिन कंपनियों ने टैरिफ का बोझ ग्राहकों पर डाल दिया था, उन्हें सोधे रिफंड दिया जाएगा नहीं। यदि उन्हें रिफंड मिलता है, तो ग्राहकों को पैसा कैसे लौटाना होगा, यह भी एक जटिल मुद्दा बना हुआ है। इन परिस्थितियों में कई कंपनियों का रिफंड अटक सकता है।

(नोट: इस लेख में ये दिए गए विचार लेखक के अपने विचार हैं)

सम्पादकीय

राज्य सरकारों पर गंभीर वित्तीय संकट

हिमाचल की सरकार का वित्तीय संकट तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक प्रकोप के कारण हिमाचल सरकार के ऊपर खर्च बढ़ा है। केन्द्र सरकार से प्राकृतिक आपदा के लिए जो सहायता मिलनी चाहिए थी वह भी नहीं मिली। दरअसल प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके फलस्वरूप हिमाचल में अब खर्च में कटौती करनी पड़ रही है। अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डगमगा गई है। मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के वेतन में कटौती की गई है। आगे चक्कर इसका असर वेतन, पेंशन विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पड़ना तय है। हिमाचल प्रदेश सरकार का बढ़ता कर्ज, सीमित राजस्व स्रोतों ने हिमाचल को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा दिया है। यह स्थिति हिमाचल तक सीमित नहीं है। देश के एक दर्जन से अधिक राज्य आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। हर माह उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। पंजाब, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। कई राज्यों का कुल ऋण उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच गया है। जो राज्यों की वित्तीय स्थिति के लिए खतरे की घंटी है। इन राज्यों की आय का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन, ब्याज, कर्ज की अदायगी और लोक लुभावन योजनाओं में खर्च हो रही है। जिसके कारण विकास योजनाओं के लिए सरकारी खजाने में राशि ही नहीं है। समस्या की जड़ में राजनीतिक लोकलुभावन नीतियां हैं। मुफ्त बिजली, सब्सिडी और नकद सहायता जैसी योजनाओं ने राज्य की आर्थिक स्थिति का कबाड़ा कर दिया है। जो आने वाले समय में राजकोषीय संतुलन को बिगाड़ रही हैं। सभी राज्य सरकारों को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। यही कर्ज धीरे-धीरे राज्यों के वित्तीय संकट के रूप में सामने आ रहा है। अमेरिका- इजरायल और ईरान युद्ध के बाद भारत सरकार का बजट भी गड़बड़ा रहा है। भारत सरकार को ऊर्जा जरूरत और अन्य जरूरत का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। केन्द्र सरकार का राजस्व घट रहा है, इसका असर भी राज्यों की आर्थिक स्थिति में पड़ना तय है। महंगाई, बेरोजगारी और आयात का बढ़ता खर्च केन्द्र सरकार के साथ-साथ वित्तीय संस्थाओं के ऊपर भी दिखने लगा है। शेयर मार्केट की गिरावट से वित्तीय संस्थानों में इसका असर दिखने लगा है। रिजर्व बैंक भी इससे अछूता नहीं है। युद्ध के कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं, ब्याजदरों में वृद्धि, विदेशी मुद्रा संकट का असर केन्द्र से मिलने वाले राजस्व में कटौती राज्यों की परेशानी बढ़ा रहा है। यदि यही स्थिति तीन-चार महीने और बनी रही, तो आने वाले महीने में कई राज्य सरकारें कर्ज और खर्च के जाल में फंस सकती हैं। कई राज्य अभी भी नया कर्ज पुराने कर्ज को चुकाने के लिए लेने को विवश हो रहे हैं। राज्यों के ऊपर जिस तरह से आर्थिक संकट बढ़ता चला जा रहा है, इस संकट से निकलने के लिए राज्यों को कठोर आवश्यक कदम उठाने होंगे। राजस्व बढ़ाने आय और व्यय के बीच में संतुलन बनाते हुए कर सुधार, के साथ-साथ गैर-जरूरी खर्चों में कटौती करना होगी। विकास योजनाओं की प्राथमिकता तय करनी होगी। सरकार को वित्तीय अनुशासन आय और व्यय के बीच में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करके वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना होगा। समय रहते सुधार के प्रयास नहीं किए गए, तो यह संकट कुछ राज्यों तक सीमित नहीं रहेगा। राज्यों की बिगड़ती अर्थव्यवस्था से देश की समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति सभी राज्यों और केन्द्र सरकार के लिए एक चेतावनी है। यदि इसे नजर अंदज किया गया, तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के बाद जिस तरह के दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहे हैं, उससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की चेतावनी दी जा रही है। जिस तरह से भारत का आयात और निर्यात प्रभावित हो रहा है, विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए की कीमत में लगातार गिरावट आ रही है।



सनत जैन
लेखक

ग्लोबल हेराल्ड

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

संजय गोस्वामी लेखक

चाहिए जब भारत देश की बात आती है तो हम ना किसी धर्म से जुड़े हैं ना किसी के बहकावे में आकर देश से धोखा करेगे क्योंकि मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारी ताकत हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए एकजुट होकर भाईचारे से रहकर देश के प्रति एक जवाबदारी होनी चाहिए जब बोजेपी ने अन्य दलों के साथ मिलकर 1998 में पहली बार गैर कॉंग्रेसी सरकार आयी तो तुरंत ही उन्होंने 11 मई 98 को पोखरण परमाणु परीक्षण कर देश को अपनी ताकत का अहसास कराया आपका सच्चा धर्म अपने देश के प्रति वधादार होना है पोखरण परमाणु परीक्षण के लिए हमारे वैज्ञानिकों को तैयारी करने और पूर्वाभ्यास करने के लिए दिन रात जुटे रहें सिर्फ डेढ़ साल का समय मिला था। इस मिशन की गोपनीयता को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। 1997 तक भारत परमाणु परीक्षण को लेकर इसे पुनः परीक्षण के लिए भारत के मशहूर वैज्ञानिक डॉ एपीजे कलाम व डॉ आर चितंबरम इसे कई बार उस समय के सरकार के पास जाकर उन्हें जानकारी दी थी लेकिन सीटीबीटी व अमेरिका ने इस मिशन को रोक दिया था जो के कारण रोक दिया गया था जब 1998 में स्व पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की सरकार आई तो इसका नेतृत्व करते महान भारतीय वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को पुरी छुट दी उन्होंने कहा आप सभी वैज्ञानिक जब चाहें तब करें मुझे एत मत बताइए कब करना है



ग्लोबल हेराल्ड

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

उन्होंने साफ कहा कि पार्टी रहे या नहीं रहे इसकी चिंता नहीं है देश सर्वोपरि है अतः आप जैसे चाहे वैसे करें देश की रक्षा सर्वोपरि है इसके लिए देश के पास परमाणु अस्त्र होना जरूरी है इसकी भनक अमेरिका को लगी इसके लिए अमेरिका ने नासा में उस समय डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को बुलाया और नासा के निदेशक पद का ऑफर दिया स्व डॉ कलाम सर ने उन्हें मना तो नहीं किया लेकिन यह मामला फंस गया बने या न बने उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि जो जानते थे मेरे लिए देश सर्वोपरि है और मैं अकेला हूँ अतः वो वहां जाकर एे जान गए कि भारत के परमाणु परीक्षण को लेकर अमेरिका ने सैटेलाइट लगा दिया है अतः भारत आने के बाद उन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की उन्होंने परमाणु परीक्षण से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को बताया कि यहां सैन्य अभ्यास की तैयारी कर उस मिशन को पूरा करने की कोशिश की जाए व यह काम सैटेलाइट जाने के ठीक डेढ़ (115) के पहले ही करना होगा बाद में इसकी खबर पाकिस्तान के गुप्तचरों ने अमेरिका को बता दिया और अमेरिका ने सैटेलाइट घुमाने की अवधि करीब आधा घंटा कर दिया इससे पहले पता चलता वैज्ञानिकों ने सेना की वर्दी पहने व आधे घंटे के अंदर ही घास फूस का मचान/छत जैसा तैयार कर निचे घुस कर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गड्डा खोदने का काम किया जिसमें परमाणु परीक्षण किया जाता है। भारत जब पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर रहा था, तो इसकी भनक किसी भी दूसरे देश को नहीं थी। यहां तक की परमाणु परीक्षण होने के बाद भी इसकी जानकारी किसी को नहीं लगी थी। भारत की सरकार के लिए उस वक्त से बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए भारत की हरकतों पर पल-पल नजर बनाए रखता था। सीआईए ने भारत पर नजर रखने के लिए अरबों खर्च कर 4 सैटेलाइट लगाए थे। 24 सितंबर 1996 को अमेरिका ने परमाणु विकसित देशों से मिलकर एक संधि सीटीबीटी यानी कांफ्रिहेन्सिव टेस्ट बैन ट्रीटी नामक एक समझौता लागू किया गया जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों करने के लिए प्रतिबंधित लागू किया गया है यह संधि अस्तित्व उस समय अस्तित्व में आई जब भारत परमाणु परीक्षण के लिए पुरी तरह से तैयार हो गया था। 1997 तक भारत परमाणु परीक्षण को लेकर इसे पुनः परीक्षण के लिए भारत के मशहूर वैज्ञानिक डॉ एपीजे कलाम व डॉ आर चितंबरम के अगुआई में इसे कई बार उस समय के सरकार के पास जाकर उन्हें जानकारी दी थी लेकिन सीटीबीटी मसौदा, अमेरिका व अन्य देशों के डर के कारण इस मिशन को रोक दिया गया था जब 1998 में एनडीए की सरकार आई तो स्व पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने इस मिशन को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को प्रोत्साहित किया जो इसका नेतृत्व कर रहे थे डा कलाम को इस मिशन को पूरा करने की पुरी छुट दी उन्होंने कहा आप सभी वैज्ञानिक जब चाहें तब परीक्षण करें मुझे एत मत बताइए कब करना है उन्होंने साफ कहा कि मेरी सरकार रहे या ना रहे है। पोखरण परमाणु परीक्षण 2- 11, मई 1998 को पोखरण राजस्थान में आयोजित किया गया था। पोखरण 2 का कोड वर्ड (नाम) ऑपरेशन शक्ति था। यह भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का दूसरा उदाहरण था। पहला परीक्षण, के कोड -का नाम स्मॉलिंग



लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

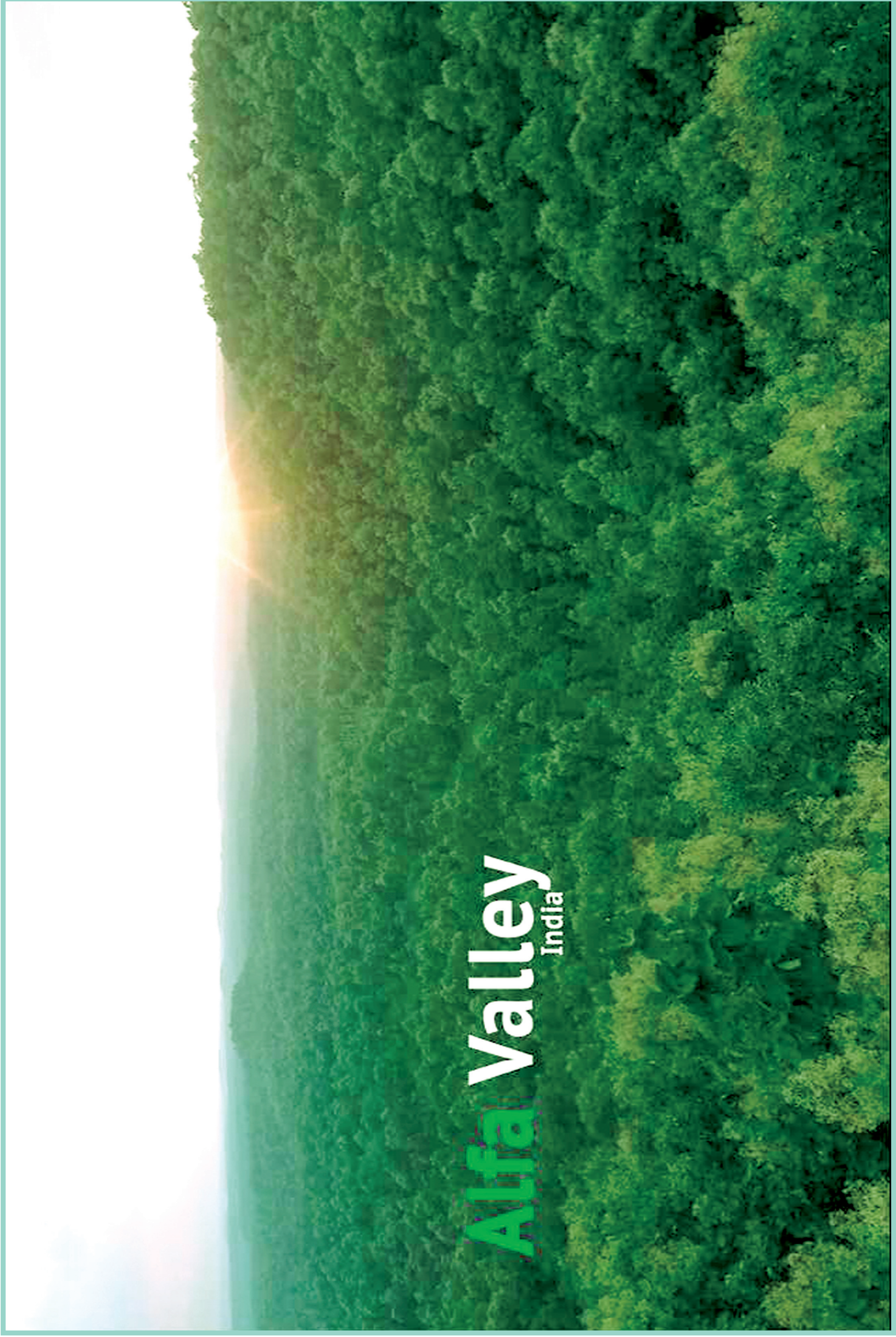
लेखक

लेखक

लेखक

लेखक

लेखक



Alfa Valley

India

